

माता पिता
जीवन देते हैं
लेकिन जीने की
कला तो शिक्षक ही
सीखाते हैं।
- अज्ञात



बगदादी का खेल खत्म

बगदादी का मकसद एक मॉडल इस्लामी राज्य कायम करके धीरे-धीरे उसका प्रसार करना था। लेकिन यह उसका सैद्धांतिक पहलू था। व्यवहार में वह पश्चिम एशिया की शिया-सुन्नी राजनीति की पैदाइश था। शियाओं के खिलाफ उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया।

निर्मला अधिकारी

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रविवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के सरगना अबू बकर अल-बगदादी को मार गिराया गया है। बगदादी के मारे जाने के दावे पहले भी किए जा चुके हैं और रूस को अब भी इस पर यकीन नहीं है। लेकिन जब ट्रंप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पुष्टि की है तो अविश्वास का कोई कारण नहीं है। ट्रंप के अनुसार अमेरिकी सेना के स्पेशल कमांडोज ने सीरिया के इदलिब प्रांत के सुदूर गांव बारिश में शनिवार की रात बगदादी के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाया। पूरी तरह घिर जाने के बाद बगदादी ने धमाका करके खुद को उड़ा लिया। इस तरह बगदादी भी उसी तरह की कार्रवाई में मारा गया जिस तरह ओसामा बिन लादेन मारा गया था।

बगदादी लादेन से बहुत प्रभावित था और उसी के नक्शेकदम पर चलते हुए उसकी मौत का बदला लेना चाहता था। इस तरह दुनिया को दो खूंखार आतंकीयों से मुक्ति मिली जिन्होंने अपने खूनी खेलों से पूरी मानवता को थर्रा दिया था। इस्लामी आतंकवाद का घृणित मुहावरा उनके कारण ही शुरू हुआ। उनके कृत्यों से इस्लाम की उदारवादी छवि कमजोर पड़ी और कई मुल्कों में मुस्लिम समुदाय को संदिग्ध छवि का शिकार होना पड़ा। बगदादी असल में वहाबी विचारधारा से प्रेरित था जिसका उद्देश्य दुनिया में इस्लामी उसूलों पर आधारित मध्यकालीन राज्य की पुनर्स्थापना बताया गया। उसने खुद को खलीफा घोषित किया और सीरिया-इराक के कई इलाकों पर अपना शासन चलाया।

बगदादी का मकसद एक मॉडल इस्लामी राज्य कायम करके धीरे-धीरे उसका प्रसार करना था। लेकिन यह उसका सैद्धांतिक पहलू था। व्यवहार में वह पश्चिम एशिया की शिया-सुन्नी राजनीति की पैदाइश था। शियाओं के खिलाफ उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। उसका संगठन इस्लामिक स्टेट शियाओं के खिलाफ गहरी नफरत से भरा था और उसने सभी गैर-सुन्नियों के खिलाफ खूनी अभियान चलाए। उसकी विचारधारा ने भारत समेत दुनिया के कई चरमपंथियों को प्रभावित किया। उससे असर में कई देशों के नौजवान इस्लामिक स्टेट जॉइन करने पहुंच गए। जो संगठन में शामिल नहीं हुए, वे निजी स्तरों पर ही कार्रवाई करने लगे। अनेक देशों में उन्होंने आतंकी

गतिविधियां संचालित कीं।

अब भी यह कहना मुश्किल है कि बगदादी के मारे जाने से आइसिस की कमर पूरी तरह टूट जाएगी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उसके मारे जाने के बाद कोई और उसकी कमान संभाल लेगा और संगठन पहले की ही तरह चलता रहेगा क्योंकि इसका एक मजबूत नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। एक कड़वी सच्चाई यह है कि कुछ ताकतवर देशों ने अपने हितों के लिए कई बार ऐसे संगठनों को हथियारों और अन्य तरीकों से सहायता दी है। अगर आतंकवाद को समाप्त करना है तो ऐसी सरकारों से भी सख्ती से पेश आना होगा। लादेन और बगदादी का हश्र बताता है कि हिंसा और अराजकता का अंत एक न एक दिन इसी तरह होना है।

अहंकार के स्रोत

शिवदाना ध्यान विचार प्रक्रिया पर चर्चा और उसे एक केंद्र बिंदु तक लाने का काम करता है। कुछ लोग संपूर्ण विचार शून्यता की बात करते हैं। दूसरा रास्ता ब्रह्म के प्रकाश को देखने के लिए भौंहों के बीच ध्यान केंद्रित करने का है। मंत्रों का जप करना भी ध्यान का एक दूसरा तरीका है। अरुणाचल के रमन महर्षि का कहना है कि किसी इंसान को अपनी पहचान को खोजने के लिए ये सवाल पूछना चाहिए कि 'मैं क्या हूँ?' ध्यान में व्यक्ति को ये सवाल करना चाहिए और फिर धीरे-धीरे विकास के क्रम में वो चैन और शांति को हासिल कर लेता है।

धर्म-दर्शन



ये सवाल सच में बेहद मायने रखता है कि अहंकार का स्रोत क्या है? इसका उत्तर हासिल करने के लिए आपको अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। इस भावना को छोड़ देना होगा कि आपका शरीर इस नाम, पेशे, क्षेत्र, भाषा और इस तरह की दूसरी पहचानों से जुड़ा है।

संपादकीय

रिजर्व का सहारा

भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांश, सरप्लस और कॉन्टिजेंसी फंड से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का जो फैसला किया है, उसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। लंबे समय से यह सवाल सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ था और इस पर जिम्मेदार अधिकारियों और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई थी। ऐसे में विमल जालान समिति की सिफारिशों की रोशनी में आरबीआई बोर्ड ने जब इतनी बड़ी राशि सरकार को सौंपने का फैसला किया है तो उस पर सवाल उठने लाजिमी हैं। खासकर इसलिए भी कि इससे पहले कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रिजर्व बैंक ने ऐसा फैसला नहीं किया था।

बहरहाल, यह कतई जरूरी नहीं है कि परिस्थिति की जटिलताओं से जूझते हुए कोई सरकार या संस्था हमेशा वैसे ही कदम उठाए जिनकी मिसाल अतीत में मौजूद हो। देखने की बात यह है कि जो कदम उठाया जा रहा है, वह कितना जरूरी है और उससे जुड़े जिन खतरों की ओर इशारा किया जा रहा है उनसे बचने की तैयारी कैसी है। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। न केवल कई उद्योगों के आंकड़े कठिन स्थिति का संकेत दे रहे हैं बल्कि सरकार की राजस्व वसूली भी उम्मीद से कम है। ऐसे में जब सरकार पर इन्फ्लैट्रक्चर में अधिक से अधिक निवेश के जरिए मांग पैदा करने का दबाव है, तब फंड की कमी उसके हाथ बांध दे रही है।

जाहिर है, इस मामले में सबसे अहम भूमिका खुद सरकार की होगी। इस आकरिमिक सहायता ने बजट घाटे से निपटना उसके लिए आसान बना दिया है, लेकिन असल चुनौती उसके सामने यह है कि रिजर्व बैंक से मिली इस राशि के जरिए वह इकॉनमी को गति कैसे दे और लोगों की नौकरियां बचाने तथा नई नौकरियां पैदा करने में कामयाबी कैसे हासिल करे।

मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल से ही बेरोजगारी बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। इन फैसलों से सरकार को बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

फील गुड फैक्टर

अनिल भट्ट

हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं को मिनी बजट कहा गया। लेकिन सरकार का रुझान अभी हर हफ्ते ही एक मिनी बजट जारी करने का जान पड़ता है। मंदी की बढ़ती आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे कई फैसले किए गए हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। बैठक में 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया, जो सीधे किसानों के खाते में जाएगी। सरकार 2021-22 तक 75 मेडिकल कॉलेज खोलेगी, जिससे देश में एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढ़ जाएंगी।

सबसे बड़े फैसले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मामले में लिए गए हैं। कोयले के खनन और उसकी बिक्री में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है। सिंगल ब्रांड रिटेल को एफडीआई के लिए अधिक आकर्षक बनाया गया है और डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल से ही बेरोजगारी बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। इन फैसलों से सरकार को बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की उम्मीद



है। एकल खुदरा ब्रांड यानी एक ब्रांड के तहत उत्पाद बेचने वाली विदेशी कंपनियां अब अपना कोई स्टोर खोले बिना ऑनलाइन सामान बेच सकती हैं। पहले कुछ समय तक रिटेल स्टोर से सामान बेच लेने के बाद ही ये ऑनलाइन कारोबार में उतर सकती थीं। 30 फीसदी घरेलू खरीद के नियम में भी उन्हें कुछ छूट दी गई है। ऐसा घरेलू खरीद की परिभाषा आसान बनाकर किया गया है। विदेशी कंपनियों द्वारा निर्यात के लिए की गई खरीद को भी घरेलू खरीद में शामिल माना जाएगा।

उनके नई फैक्ट्री लगाने के पहले और उसके बाद की गई खरीद को भी इसी सीमा में लिया जाएगा। ठेके पर कराई जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग के रूप में घरेलू बाजार से जो खरीद होती है, उसे भी घरेलू खरीद ही माना जाएगा। मोदी सरकार ने वैश्विक परिस्थितियों को भांपकर ही एफडीआई के नियमों में इतने खुलेपन की गुंजाइश बनाई है।

सरकार अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर का भरपूर फायदा उठाना चाहती है। उसके इन फैसलों से उन कंपनियों को भारत में निवेश का मौका मिलेगा, जिनके लिए चीन में अपना कारोबार चलाना दिनोंदिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसी कंपनियों को भारत में आने का खुला न्योता दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और काम के मौके बढ़े तो बाजार में नई मांग पैदा होगी। मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला सोशल डिवेलपमेंट के लिहाज से अहम है। फिलहाल देश में 11,082 की आबादी पर मात्र एक डॉक्टर है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह अनुपात प्रति हजार व्यक्तियों पर एक होना चाहिए। नए मेडिकल कॉलेजों से हेल्थ सेक्टर की दशा बेहतर होगी। अर्थव्यवस्था के लिए ये फैसले फील गुड फैक्टर साबित हो सकते हैं।

सूदुंकु नवताल- 5153		*** ** *	
5	9	8	3
2	4		8
3	8	5	2
7			9
9	3	6	8
2	6		1
	5	2	7
6		4	7
	8	9	6
		4	2

अपना ब्लॉग तकनीकी की रेलमपेल

चंद्रभूषण टेक्नॉलजी की उठापटक के मामले में नब्बे का दशक अद्वितीय समझा जाएगा। कोई चीज आसमान से उतर कर अचानक जमीन पर छा जाती। फिर देखते-देखते ऐसे गायब होती जैसे गधे के सिर से सींग। इन बदलावों के पीछे हजारों-लाखों परिवारों की बर्बादी की कहानी भी मौजूद होती, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान मुश्किल से ही जा पाता था। 1990 में मैंने दिल्ली में पेजर का चलन शुरू होते देखा था, जो जल्द ही किसी फैंशन स्टेटमेंट की शक्ल ले बैठा। टी-शर्ट तब कम लोग पहनते थे। पैंट में खुंसी कमीज, चौड़ी बेल्ट और उस पर सामने दाईं तरफ सजा अल्फा-न्यूमेरिक पेजर। महानगरों में किराये पर रहते हुए घूम-फिरकर दिहाड़ी मारने वाले पेजरधारी शाम को ठिकाने पर पहुंचते तो उन्हें पता चल जाता कि उनसे कौन, कहाँ, किस नंबर पर संपर्क करना चाहता था। नए-नए पीसीओ बूथ भी उसी समय खुले थे, जहां बटन वाले फोन पर अगले दिन का प्रोग्राम फिक्स हो जाता था। इस पेजर और पीछे-पीछे पीसीओ बूथ को भी भारतभूमि पर आने और यहां से जाने में बमुश्किल दस साल लगे।

पीएम मोदी ने कहा हम खाते ज्यादा हैं, और मेहनत कम करते हैं।

कम खाया
करो, तभी
फिट रहोगे...

